Telangana Today- 03- November-2022

# Need for equitable water agreements: Rawat

STATE BUREAU
Hyderabad

Former secretary of Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Alok Rawat, stated that to resolve water-sharing disputes among various States, there was a need for equitable inter-State and intra-State river water agreements.

Delivering the keynote address on the topic 'Preventing water wars in Global and Indian perspective' at the India Water Week- 2022 at India Expo Centre, New Delhi, on Wednesday, Rawat stressed the need for controlled exploitation of groundwater.

**Focus should be shifted**

Central Water Commission (CWC) former member Chetan Pandit stated that the focus of river water sharing should be shifted from inter-boundary transfer to in-basin requirements on priority.

He stated that a large quantity of water from Krishna basin was diverted to the outside basin by the undivided Andhra Pradesh of its allocation, and it was one of the main reasons for the division of the State and formation of Telangana.

Pandit said that inter-basin transfers without addressing the in-baisn needs would lead to a dispute between the regions based on prescriptive rights and riparian rights.

In another session, Telangana Irrigation Department Chief Engineer V Mohan Kumar presented a power-point presentation about "Strategies for demand and supply side management".

**TS initiatives**

Chetan Pandit presented various initiatives of Telangana government in Mission Kakatiya, Rythu Bandhu, use of Technology, prioritised projects, modernisation and re-engineering of projects and groundwater management, Telangana Ku Haritha Haram, State Level Committee for Integrated Water Planning and Management, and Piped Irrigation to achieve creation of irrigation potential of 1.25 crore acres in the shortest possible time frame.

The Hindu- 03- November-2022

# Water released from Red Hills, Chembarambakkam lakes

The Water Resources Department on Wednesday released 100 cusecs of water each from Chembarambakkam and Red Hills reservoirs. This was due to heavy rainfall in the catchment areas of both the waterbodies and as a precautionary measure. In Chembarambakkam, the water gushed out via the 6.5-km-long surplus course and joined the Adyar at Thirumudivakkam. Residents of low-lying areas along the route were warned of flood and were told to move to safe places.

**Dainik Jagran- 03- November-2022**

# सतत विकास के लिए एक साथ आने की जरूरत : गजेंद्र सिंह शेखावत

- इंडिया वाटर वीक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जीएस शेखावत व केंद्रीय राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ने सत्र को किया संबोधित
- डेनमार्क और भारत के विशेषज्ञों के बीच स्थायी जल प्रबंधन में सहयोग, जल अनुसंधान विकास आदि पर हुई चर्चा

इंडिया वाटर वीक में सत्र को संबोधित करते केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ● जागरण

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा : इंडिया वाटर वीक के दूसरे दिन बुधवार को पहले सत्र में भारत और डेनमार्क के विशेषज्ञों के बीच चर्चा हुई। स्थायी जल प्रबंधन में सहयोग, जल अनुसंधान विकास आदि पर विचार विमर्श हुआ। जल शक्ति मंत्रालय में सचिव पंकज कुमार व भारत में डेनमार्क के राजदूत फ्रेडी स्वेन मौजूद थे। अन्य सत्र में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्यमंत्री कैलाश चौधरी शामिल हुए।

डेनमार्क के प्रतिनिधियों ने कहा कि वह भारत सरकार के साथ मिलकर जल संरक्षण और नदियों को साफ करने का कार्य करेंगे। उनके यहां भी भारत जैसी ही स्थिति थी। उनकी नदियां भी गंदी थीं, पर तकनीक का प्रयोग कर ग्रे वाटर प्रबंधन से 90 प्रतिशत पानी को साफ किया गया। 95 प्रतिशत पानी को दोबारा इस्तेमाल के लायक बनाया गया। डेनमार्क में एक भी ओवरहेड टैंक नहीं बना है। डेनमार्क की हे नदी का उदाहरण पेश किया गया। 2019 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ डेनमार्क ने द्विपक्षीय समझौता किया था। इसी के तहत डेनमार्क अपनी तकनीक भारत को देकर उसकी जरूरतों को पूरा करेगा। तमिलनाडु और खास तौर से हिमाचल प्रदेश के कुछ जगहों पर प्रायोगिक तौर पर काम शुरू किया है। सेंसर आधारित तकनीकी से डेनमार्क भारत में पेयजल उपलब्धता पर विशेष ध्यान देगा। जल शक्ति मंत्रालय के सचिव पंकज कुमार ने जल जीवन मिशन के कार्यों, भूजल स्तर, ग्रामीण शुद्ध पेयजल उपलब्धता व जल के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने, विविध हितग्राहियों को एक साथ लाने, जल संरक्षण में नवाचार को बढ़ावा देने पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि जल जीवन मिशन योजना के तहत हर घर में पानी पहुंचाने का प्रयास हो रहा है, पर अभी और काम करने की जरूरत है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पेयजल की शुद्धता के मानक को सिद्ध करने के लिए 'हर घर में नल और नल से जल मिशन' की सफलता व शुरू किए गए स्टार्टअप के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भौगोलिक अंतर पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय सतत विकास के लिए एक साथ आने की जरूरत है।

ओडीएफ पहल का लक्ष्य 2019 तक सफलतापूर्वक पाया गया, जिसे 2030 तक पाने का लक्ष्य तय था। कैलाश चौधरी ने कहा कि आज के समय में पानी का सबसे अधिक उपयोग खेती में हो रहा है। विश्व की कुल भूमि का 328 मिलियन हेक्टेयर हिस्सा भारत का है। कुल पानी का चार प्रतिशत भारत में है, जबकि आबादी 18 प्रतिशत है, जिसमें 50 प्रतिशत क्षेत्र सिंचित क्षेत्र के अंदर आता है। आज देश में 70 लाख हेक्टेयर भूमि पर सूक्ष्म सिंचाई से खेती की जा रही है। 2016 से लगातार भारत सरकार द्वारा सूक्ष्म सिंचाई पर काम किया गया। इससे ही पानी को बचाया जा सकता है। पाली हाउस और ग्रीन हाउस खेती के लिए सरकार की तरफ से 50 प्रतिशत की सब्सिडी किसानों को दी जा रही है। आइसीआर ने लगभग 1951 किस्म की फसल तैयार की हैं, जिसमें पानी की कम आवश्यकता होती है।

**Dainik Jagran- 03- November-2022**

# जल पर टिका देश के शहरों का 'कल'

जल है तो कल है। भविष्य सुरक्षित रखना है तो जल संचयन करना ही होगा। ग्रेटर नोएडा में इंडिया वाटर वीक में जल संरक्षण और संचयन पर इस समय मंथन चल रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अनुसार भूजल स्तर गिरने से देश में जल संकट और गहराया है। दूर दराज के क्षेत्र ही नहीं बड़े शहर भी पानी के लिए हांफते दिख रहे हैं। आइए समझें क्या है देश के शहरों में पानी की स्थिति और आने वाले आठ-दस वर्षों में कैसा दृश्य बन सकता है:

**2030** तक देश में जल की मांग उपलब्धता से दोगुनी हो जाएगी

**2050** तक देश के 30 शहरों में भीषण जल संकट की आशंका वर्ल्ड वाइड फंड ने जाहिर की है

**2024** तक देश के सभी घरों तक नल से जल पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन के अंतर्गत काम तेजी से चल रहा है

**135** लीटर पानी की आवश्यकता भारत में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन विशेषज्ञों के अनुसार होती है

**67.3%** शहरी घरों के पास सीवर लाइन से नहीं जुड़े हैं। इस कारण भूजल की गुणवत्ता पर भी प्रभाव पड़ता है

**50%** के आंकड़े से देश के अधिकांश अधिक जल उपलब्धता सूचकांक में नीचे पाए गए

**48%** शहरी जलापूर्ति का माध्यम भारत में भूजल ही है। इसके गिरते स्तर से शहरों में जल संकट गहरा रहा

**40%** जनसंख्या के वर्ष 2030 तक भारतीय शहरों में रहने का अनुमान है

**31%** शहरी घरों के पास पाइप वाले पानी की आपूर्ति की व्यवस्था नहीं है

**6%** की कमी भारत की जीडीपी में होने की आशंका जल संकट के कारण है

**20** वर्ष में भारत के जलभृत यानी भूजल उपलब्ध कराने वाले स्रोत की स्थिति अत्यधिक चिंताजनक होने की आशंका है

**21** शहरों में उपलब्ध जल के नमूने बीते वर्ष शुद्धता के मानक पर खरे नहीं उतरे थे

## ...जब चेन्नई ने चेताया

- वर्ष 2019 की गर्मियों में चेन्नई शहर को अभूतपूर्व जल संकट का सामना करना पड़ा था। तमिलनाडु की सरकार को इस संकट से निपटने के लिए एक करोड़ लीटर पानी की व्यवस्था टैंकरों के माध्यम से करनी पड़ी थी।
- चेन्नई की यह समस्या बाकी शहरों के लिए भी एक चेतावनी की तरह है क्योंकि इस शहर में प्रतिवर्ष 1,400 मिलीमीटर वर्षा होती है। लंदन शहर से यह मात्रा दोगुनी है, फिर भी चेन्नई को भीषण जल संकट का सामना करना पड़ा था।

## शहरों में क्यों बढ़ रहा जलसंकट

- देश के शहरों में चेन्नई की तरह ही जलसंकट वर्ष दर वर्ष बढ़ रहा है। 'नेचर' के एक अध्ययन के अनुसार वर्ष 2050 तक राजस्थान का जोधपुर सर्वाधिक जल संकट वाला विश्व का दूसरा शहर होगा।
- शहरों में जल संकट बढ़ने के प्रमुख कारणों में जनसंख्या वृद्धि व तेजी से हो रहा अनियोजित शहरीकरण प्रमुख हैं। बिना योजना के बस रहे शहरों व नए क्षेत्रों में जलापूर्ति पर अधिक विचार नहीं किया जा रहा। भूजल का अंधाधुंध दोहन भी शहरों में इस समस्या को बढ़ा रहा है।
- देश के केंद्रीय जल आयोग की पड़ताल में सामने आया कि देश के 91 महत्वपूर्ण जलाशय में हालिया वर्ष में अपनी क्षमता के आधे से अधिक नहीं भर सके हैं।

**32,000** करोड़ रुपये वर्ष 2014 से 2018 तक प्रतिवर्ष जल संरक्षण पर देश में खर्च किए गए

**60** करोड़ लोगों को देश में जल की कमी का सामना करना पड़ता है

**61%** तक गिरावट देश के भूजल स्तर में वर्ष 2007 से 2017 के बीच दर्ज की गई है

**4,378** शहरी निकायों के 2.86 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचाने की योजना पर तेजी से काम चल रहा है

**75** तालाब देश के हर जिले में अमृत सरोवर योजना के तहत बनाए जाने हैं। यह लक्ष्य अगले वर्ष स्वतंत्रता दिवस तक पूरा किया जाना है

स्रोत: नीति आयोग, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ, सीएसई, केंद्रीय जलशक्ति मंत्रालय

**Rajasthan Patrika- 03- November-2022**

**साक्षात्कार :** पर्यावरणविद पद्मभूषण और पद्मश्री डॉ. अनिल प्रकाश जोशी

# जल संग्रहण ही प्रकृति का मूल स्वरूप पाने का रास्ता

*जलवायु संकट से दुनिया को बचाने के लिए आर्थिक विकास और प्रकृति के बीच संतुलन की जरूरत आज हर तरफ महसूस की जा रही है। यह संतुलन कायम करने के लिए देश के हर नागरिक तक प्रकृति को बचाने का संदेश पहुंचाने के लिए ही गत 2 अक्टूबर को पर्यावरणविद पद्मभूषण और पद्मश्री डॉ. अनिल प्रकाश जोशी ने मुंबई से 'प्रगति से प्रकृति पथ' यात्रा की शुरुआत की। करीब 2000 किलोमीटर की यह साइकल यात्रा 9 नवंबर को देहरादून पहुंच कर संपन्न होगी। बुधवार को यात्रा दिल्ली पहुंची। प्रस्तुत हैं डॉ. जोशी से अब तक की यात्रा को लेकर उनके अनुभवों पर **नितिन मित्तल** की खास बातचीत के चुनिंदा अंश:*

**Q *आपने पर्यावरण संरक्षण का संदेश जन-जन तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। अब तक की यात्रा के बाद क्या अनुभव कर रहे हैं?***

महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, राजस्थान के धौलपुर, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से जैसे झांसी, आगरा और हरियाणा के फरीदाबाद के बाद दिल्ली तक की यात्रा में कुछ अद्भुत और अलग से अनुभव हुए हैं जो मैं साझा करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी बात यह है कि देश में जिस तरह की विभिन्नताएं हैं उनके लिए देश को शत-शत प्रणाम। दूसरी बड़ी बात यह है कि पिछले 20 सालों में निश्चित रूप से देश में बड़े बदलाव आए हैं। भारत आगे बढ़ रहा है। इस बात का आधार यह है कि 2008 में भी मैंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा की थी और इस यात्रा के दौरान कई इलाकों को दोबारा देखने का मौका मिला, खास तौर से चम्बल और मुरैना के गांव।

**Q *पर्यावरण को लेकर कोई ऐसा सवाल, जो महाराष्ट्र हो या मध्य प्रदेश, हर प्रदेश के हर गांव के समक्ष यक्षप्रश्न बनकर खड़ा हो?***

सभी राज्यों में सामूहिक रूप से एक बड़ा सवाल बना हुआ है। यह सवाल पानी को लेकर चिंता के रूप में है। शहर हों या घर-गांव, सभी एक साथ पानी की कमी देख रहे हैं, झेल रहे हैं। सभी जगह इस बात की स्वीकार्यता थी कि पानी का संकट सामने है। और इसका बड़ा कारण है वनों का बढ़ता अभाव। महाराष्ट्र में वनों का बहुत अभाव था, मध्यप्रदेश में इसकी कुछ झलक थी पर आगे बढ़ते-बढ़ते वनों की कमी कहीं न कहीं दिखाई दी है। वन और पानी दोनों एक-दूसरे से हैं, जल होगा तो वन पनपेंगे और वन होंगे तो जल। अभी हमारी समझ में कहीं एक चूक दिखाई देती है कि पहले जल है और उसके बाद पेड़ और वन। आज यह महसूस कराया जाना जरूरी है कि हम पहले जल संचयन-संग्रहण की बड़ी तैयारी करें तो शायद प्रकृति को उसके पहले जैसे स्वरूप में लौटाने का तुरंत एक बड़ा रास्ता तैयार कर सकते हैं।

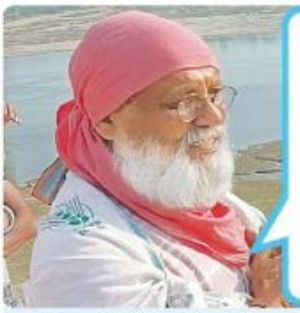

**Q *जल संकट से लेकर प्रकृति और प्रगति के संतुलन तक पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार के लिए क्या जनजागरूकता कोई असर छोड़ पा रही है?***

लोग प्राचीन जलस्रोतों का महत्त्व समझ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पहले गांव तालबेहट (झांसी) में एक वेटलैंड है जिससे स्थानीय लोगों की आय भी जुड़ी हुई है। जरूरत है कि हम ऐसी वाटर बॉडीज को नए आयामों के साथ जोड़कर देखें ताकि इन जलस्रोतों का सदुपयोग हो, समुचित उपयोग हो। पूरी यात्रा के दौरान एक बात बहुत अच्छी लगी, वह यह कि लोग स्वीकार करने लगे हैं उन्हें पानी के संग्रहण को लेकर पुराने तौर-तरीकों के जरिए ही स्थायी समाधान मिल सकते हैं।

**Q *जलस्रोतों के पुनर्भरण और जल संग्रहण के लिए पहला कदम क्या होना चाहिए?***

नदियां चाहे मध्यप्रदेश की हों, चाहे महाराष्ट्र की, खत्म होते पानी और प्रवाह से आने वाले समय में गंभीर हालात पैदा होंगे। पहला कदम यह होना चाहिए जिसकी रास्ते भर चर्चा भी की गई कि नदियों के जलागमों (वाटरशेड) को जल छिद्रों से आच्छादित कर दिया जाए। इस तरह वर्षा जल इन जल छिद्रों के माध्यम से स्वत: ही नदियों को दोबारा सींच देगा। हर वर्ग से बहस और बातचीत में इसके प्रति स्वीकार्यता भी आई है। बुंदेलखंड जो आज जल अभाव के लिए जाना जाता है, अनेक नदियों का क्षेत्र भी है और कभी इस क्षेत्र में हजारों तालाब हुआ करते थे। अब लोग इन तालाबों के उद्धार के लिए कमर कसने को तैयार हो रहे हैं।

**Q *रोजमर्रा के जीवन में व्यस्त लोग क्या जलवायु परिवर्तन के संकेत समझ पा रहे हैं?***

हर स्तर पर चर्चा हुई, राजनीतिक स्तर पर भी। एक बात सबने स्वीकारी कि जिस तरह से मौसम में बदलाव हो रहे हैं और यह दिखाई भी देता है कि अक्टूबर के महीने का तापक्रम अप्रेल-मई के तापक्रम से कम नहीं है, यह इशारा है कि अब आने वाले समय में अगर हम चेते नहीं तो हमारे लिए मौसम की पहचान करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि तब अक्टूबर में जुलाई जैसी बारिश सामान्य बात होगी। सभी राज्यों में वर्षा के बदलते रुख को सब ने महसूस किया है। खेती-बाड़ी पर इसका बड़ा असर पड़ा है और किसान किसी न किसी रूप में आहत थे। इस बदलते और बढ़ते भारत के साथ कहीं ज्यादा बड़ी चिंता प्रकृति के बदलाव और घटते वन-घटते जलस्रोतों के रूप में सामने आई है।

**Q *इन पर्यावरणीय चुनौतियों का क्या कोई समाधान आप देख पा रहे हैं?***

यात्रा के दौरान यह धारणा मजबूत हुई है कि देश में एक बड़ी पहल की आवश्यकता है, एक बड़ी चर्चा की आवश्यकता है जो प्रकृति और प्रगति दोनों को एक साथ नापे-तोले और उसी से आगे बढ़ने के रास्ते हों जिससे शायद संतुलन तय हो पाएगा। जहां-जहां किसान चेते हुए थे, जहां-जहां लोग इस संतुलन के अभाव को समझ रहे थे उन्होंने अपने प्रयोगों, अपने तरीकों से इसे साधा। उदाहरण के लिए, नासिक के पास चांदवाड में करीब 350 साल पुराना एक तालाब लगभग खत्म हो चुका था पर पानी की किल्लत को देखते हुए स्थानीय लोगों ने ही उसे पुनर्जीवित किया और आज वह पानी कई एकड़ खेती-बाड़ी का सिंचाई स्रोत बन गया है। ऐसे कई चमत्कार भी यात्रा के दौरान देखने को मिले।

**Q *अंतिम रूप से यात्रा का उद्देश्य आप किस रूप में पूरा होता हुआ देखते हैं?***

अब तक की यात्रा का सबसे सुखद अनुभव यह रहा कि लोगों में कहीं न कहीं ये जानकारियां जगह बना रही हैं। यात्रा अभी उत्तर प्रदेश के एक हिस्से से गुजरेगी और उत्तराखंड जाएगी। इस यात्रा के तमाम अनुभव जुटाकर राष्ट्रीय स्तर पर हमारी क्या नीति प्रकृति के प्रति होनी चाहिए, उस पर बातचीत होगी और सभी हितधारकों को सहमति के साथ एक मंच पर लाने की कोशिश होगी।

Hindustan- 03- November-2022

# अच्छी पैदावार वाली फसलों पर जोर

- मंत्री बोले, सरकार पानी संकट का समाधान ढूंढ़ रही
- लक्ष्यों को पाने के लिए एक साथ आना जरूरी

**ग्रेटर नोएडा, संवाददाता।** इंडिया एक्सपो मार्ट सेंटर में चल रहे भारत जल सप्ताह (इंडिया वाटर वीक) के दूसरे दिन बुधवार को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 'हर घर में नल और नल से जल मिशन' शुरू किया गया।

कार्यक्रम में बताया गया कि सरकार कम पानी में अच्छी पैदावार देने वाली फसलों को बढ़ावा दे रही है। मंत्री ने कहा कि ओडीएफ का लक्ष्य वर्ष 2019 तक सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया गया। जबकि, इस पाने का लक्ष्य वर्ष 2030 तक निर्धारित किया गया था। इसे पूरे देश के एकीकृत और समग्र दृष्टिकोण के साथ हासिल किया गया। उन्होंने कहा कि भौगोलिक अंतर पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय सतत विकास लक्ष्यों को पाने के लिए एक साथ आना जरूरी है। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि पानी का सबसे अधिक इस्तेमाल खेती के लिए किया जाता है।

आज विश्व की लगभग 328 मिलियन हेक्टेयर भूमि भारत में है। विश्व के कुल पानी का चार प्रतिशत पानी भारत में है, जबकि आबादी 18 प्रतिशत है। 50 प्रतिशत पानी सिंचित क्षेत्र के अंदर आता है। पॉली और ग्रीन हाउस खेती के लिए सरकार की तरफ से 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है।

**Rashtriya Sahara- 03- November-2022**

# जल पर चिंता

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 'इंडिया वाटर वीक' में अपने संबोधन में जिन चिंताओं का इजहार किया है, उन्हें वैज्ञानिकों, नगर नियोजकों और नवोन्मेषकों को चुनौती के तौर पर स्वीकार करना चाहिए। तकनीक विकसित करने का प्रयास करके जल संसाधनों के संरक्षण में मदद करनी चाहिए। जल संरक्षण में प्रौद्योगिकी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। महामहिम का यह कथन पूर्णतया सत्य है। बढ़ती आबादी के लिए स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना वर्तमान समय में सरकारों के लिए बड़ी चुनौती है, जिससे समाज के सभी वर्गों के सहयोग के बिना पार नहीं पाया जा सकता। भावी पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रभावी जल संरक्षण जरूरी है। आम लोगों, किसानों, उद्योगपतियों और बच्चों को जल संरक्षण को अपने दैनिक जीवन में व्यवहार का हिस्सा बनाना होगा। राष्ट्रपति का यह कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि बढ़ती

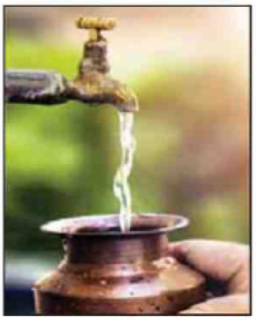

आबादी के कारण हमारी नदियों और जलाशयों की स्थिति बिगड़ रही है, गांवों के तालाब सूख रहे हैं, और कई स्थानीय नदियां तो विलुप्त ही हो गई हैं। सच है कि खेतीबाड़ी और उद्योगों में पानी का अत्यधिक दोहन किया जा रहा है। पृथ्वी पर पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है, मौसम का मिजाज बदल रहा है, और बेमौसम अत्यधिक वर्षा आम हो गई है। ऐसे हालात में सभी को जल संरक्षण के प्रति जागरूक हो जाना चाहिए। आज स्वच्छ जल की उपलब्धता पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ी जरूरत है। इस तरह यह राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा मुद्दा बन चुका है क्योंकि उपलब्ध मीठे पानी की मात्रा दो या दो से अधिक देशों के बीच ही फैली हुई है। इसलिए संयुक्त जल संसाधन ऐसा मुद्दा है जिसके लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है। देश में लगभग 80 प्रतिशत जल संसाधनों का उपयोग कृषि कार्यों में किया जाता है। चूंकि बेमौसम भारी बारिश अब आम बात हो गई है, इसलिए बारि के पानी का प्रबंधन करना भी जरूरी उपाय है। ऐसी फसल उगाई जाएं जिनमें पानी की खपत कम हो। गुजरात का सौराष्ट्र क्षेत्र अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण जल के अभाव वाला क्षेत्र था। जल प्रबंधन के उपायों के कारण अब इस इलाके की तस्वीर ही बदल गई है। ऐसे प्रयोग पूरे देश में किए जाने जरूरी हैं ताकि देशवासियों को राहत मिल सके।